P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-1* ISSUE-11* February- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभप्रदता का प्रबन्धन

शिवाली चौहान
विभागाध्यक्ष,
वाणिज्य विभाग,
रमा जैन कन्या महाविद्यालय,
नजीबाबाद

अंकुर अग्रवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
रमा जैन कन्या महाविद्यालय,
नजीबाबाद

सारांश

आज के राष्ट्रीय बैंक के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि सभी बैंक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और कैश लैस के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और इसी वजह से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से इसके ब्याज से होने वाली आयों में लगातार कमी आ रही है लेकिन आगामी वर्षों में अत्यधिक लाभ होने की सम्भावनायें हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। किसी व्यवसायिक बैंक की आय राजस्व और लागत सम्बन्धी कारकों के फलस्वरूप होती है। राजस्व सम्बन्धी कारक यह दर्शाता है कि बैंक की कुल आय उसके द्वारा की गई सेवाओं से प्राप्त होती है। लागत सम्बन्धी कारक उन समस्त खर्चों को दर्शाता है जो बैंक के द्वारा की गयी सेवाओं को करने में हुए हैं। किसी व्यवसायिक बैंक के प्रवर्ती राजस्व का मुख्य स्रोत उसके द्वारा दिये गये ऋण (उधार) पर ब्याज और कटौती, निवेश पर लाभांश, जमा खातों के सेवा प्रभार और बैंक की फीस तथा अन्य सेवा प्रभारों के द्वारा अर्जित आय होती है। किसी बैंक का व्यय भार उसके द्वारा किये जा रहे वेतन भुगतान, मजदूरी, ब्याज की अदायगी जमापूँजी की देनदारियाँ और चालू प्रवर्ती खर्चे हैं। बैंक के व्यय के समक्ष उसकी प्रवर्ती राजस्व की अधिकता को इस सम्बन्ध से जोड़ कर देखा जाता है कि बैंक की प्रवर्ती आय कर के समक्ष वास्तविक प्रवर्ती आय क्या है? यदि शुद्ध प्रवर्ती आय को शुद्ध अप्रवर्ती आय में जोड़ दिया जाये और अप्रवर्ती राजस्व की अधिकता में से अप्रवर्ती व्यय को घटा दिया जाये तब बैंक की शुद्ध आय प्राप्त हो जायेगी, जिसको करों के भुगतान के बाद प्रबन्धकीय उपयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, सी0आर0आर बैलेंस, काल मनी, निवेश

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विस्तृत आय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ब्याज से प्राप्त होने वाली आय, बिना ब्याज से प्राप्त होने वाली आय। ब्याज से प्राप्त होने वाली आय बैंकों के अग्रिम धन से प्राप्त होने वाली आय, निवेश, काल मनी के उधार देने, भारतीय रिजर्व बैंक के बैलेंस और विदेशों में किये गये पूँजी निवेश आते हैं।[1] इसको चार वर्गों में बाँटा जा सकता है– सी0आर0आर बैलेंस, काल मनी, निवेश, उधार और अग्रिम। प्रत्येक बैंक को अपने स्रोतो का एक निश्चित भाग नकद राशि के रूप में रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि बैंक को यह नकद भण्डार जमाकर्ताओं की माँग की संतुष्टि हेतु रखना पड़ता है। जितना नकद भंडार बड़ा होता है उतना ही अधिक परिसम्पत्तियों का निस्तारण होता है। बैंक अपने सम्पूर्ण स्रोतों को नकद राशि के रूप में नहीं रख सकता है क्योंकि यदि यह ऐसा करता है तो यह अपने शेयरधारकों से लाभ नहीं कमा पायेगा। इसी कारण से स्रोतों का केवल एक भाग नकदी के रूप में रखना होगा। बैंक अपने नकद भण्डार का एक भाग अन्य बैंक या देश के सेन्ट्रल बैंक में जमा कर सकता है। आपात स्थिति में बैंक अपनी नकद राशि को अन्य बैंकों से निकाल सकता है। सामान्यतः कुल जमापूँजी का 9 से 11 प्रतिशत नकद राशि के रूप में रखा जाता है।[2] यह एक दिन की अवधि के लिए धन उधार लेने और देने का तरीका है।[3] इसके अन्तर्गत वे कर्ज आते हैं, जो व्यापारियों को बहुत कम अवधि के लिए बैंक द्वारा दिये जाते हैं। ये कर्ज एक या दो दिन अथवा अधिकतम पन्द्रह दिनों के लिए दिये जाते हैं। इसी कारण से इनको 'काल मनी' के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कर्ज को बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के वापस मांग सकता है। यदि ये कर्ज समय पर बैंक को वापस प्राप्त नहीं होते हैं तो बैंक ऋणकर्ताओं की प्रतिभूतियाँ बेचकर अपनी क्षतिपूर्ति कर सकता है। ऐसे ऋणों पर बैंक बहुत कम ब्याज दर लगाता

है। यह ब्याज दर 1/2 या 1/4 प्रतिशत के बीच होती है। शेयरधारकों, दलालों और भुगतान गृहों को सामान्यतः इस प्रकार के कर्ज की आवश्यकता होती है। ये कर्ज अत्यधिक निस्तारित और सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के लिए आदर्श कर्ज होते हैं। काल मनी ने निस्तारण की दृष्टि से नकद राशि का स्थान प्राप्त कर लिया है। वास्तव में काल मनी नकद राशि से भी बेहतर परिसम्पत्ति है क्योंकि यह निस्तारण ही उपलब्ध नहीं कराती है बल्कि बैंकों की आमदनी का एक अच्छा मार्ग भी है। अल्प अवधि के कर्ज परिश्चम के देशों में अत्यधिक लोकप्रिय है किन्तु भारत में कुछ महानगरों को छोड़कर इन्हें अपेक्षाकृत असमान्य समझा जाता है।[4] जबकि बैंक लोन्स अल्प अवधि के होते हैं, यदि कहें, कुछ महीनों के लिए या एक अथवा दो वर्ष के लिए, तब निवेश अधिक लम्बे समय के लिए होता है। बैंक का निवेश सामान्यतः सरकारी बन्धक पत्रों या नियत ब्याज–प्रदत्त ऋणपत्रों या प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानों के बन्धक पत्रों के रूप में होता है। किसी बैंक का निवेश दो प्रकार का हो सकता है– अलाभकारी निवेश, लाभकारी निवेश

ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि बैंक की निधि को किस प्रकार अलाभकारी निवेश में लगाया जाना चाहिए। इन मुद्दों का निर्धारण करते समय, प्रत्येक बैंक को सुरक्षा और लाभ के दो विरोधाभासी सिद्धान्तों के बीच समझौता करना पड़ता है। बैंक का अलाभकारी निवेश सुरक्षा और स्रोतों के निस्तारण की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बैंक को अपनी निधि का एक भाग अलाभकारी निवेश के लिए निर्धारित करना होता है, जैसे कि भलीभांति ज्ञात है, बैंक का मुख्य उद्देश्य अपने लिए अधिकतम लाभ कमाना होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अधिकतम लाभ कमाने के प्रयास में बैंक जमाकर्ताओं की सुरक्षा की बलि चढ़ा दे। वास्तव में बैंक को सुरक्षा और लाभ के दो विपरीत ध्रुवों के बीच से समुचित मार्ग निकालना होता है। इस प्रकार से बैंक को अपने स्रोतों का वितरण लाभकारी और अलाभकारी निवेश में बुद्धिमता और सावधानीपूर्वक करना होता है। अलाभकारी निवेश निम्नलिखित होते हैं– संचित नकदी, डैड स्टॉक

ऋण और अग्रिम एक निवेश के रूप में

ऋण और अग्रिम राशि देने के कई उपाय हैं जो कि ऋणकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बदले दिये जा सकते हैं। बैंक इन ऋणों और अग्रिम धन से पर्याप्त मात्रा में ब्याज कमाता है। ये ऋण और अग्रिम व्यक्तियों और व्यापारिक कम्पनियों को दिये जाते हैं। बैंक सामान्यतः इन पर 6 से 12 प्रतिशत की ब्याज दर लगाती है। पश्चिमी देशों के वाणिज्यिक बैंक अपनी जमापूँजी का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा ऋणों और अग्रिम राशि देने के लिए निर्धारित करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के ऋण और अग्रिम बैंक की मांग पर अदा करने पड़ते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से बैंक इनकी मांग नहीं करता और इसको ग्राहकों के ऊपर छोड़ देता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार इनको अदा करें। तो भी इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि बैंक अग्रिम राशि देने में खतरा मोल लेते हैं। इस प्रकार ऋण और अग्रिम धनराशि देते समय बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

ऋण और अग्रिम

बैंक की सभी परिसम्पत्तियों में सबसे अधिक लाभदायक सम्भवतया ऋण और अग्रिम धनराशियाँ होती है। बैंक उद्योग और व्यापार को ऋण और अग्रिम या तो विनिमय पत्रों के भुगतान या ओवर ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान करता है। इसमें मांग और अवधि ऋण, परोक्ष ऋण और सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए दिया गया अग्रिम धन सम्मिलित होता है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी निवेशित राशि का एक निश्चित भाग अपने ग्राहकों को ऋण और अग्रिम देने के लिए निर्धारित करता है। ऋण और अग्रिम के कई पकार हैं जो ऋणदाताओं की विभिन्न प्रतिभूतियों के सापेक्ष दिये जाते हैं। बैंक उन ऋणों और अग्रिमों से पर्याप्त रूप से ब्याज कमाता है जो व्यक्तियों और वाणिज्यिक इकाईयों को प्रदान किये जाते हैं।[5] सामान्यतः बैंक ऐसे ऋणों और अग्रिमों से 6 से 12 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करता है। पश्चिमी देशों के वाणिज्यिक बैंक अपनी जमापूँजी का 50 से 60 प्रतिशत तक ऐसे ऋणों और अग्रिमों के लिए निर्धारित करते हैं। ये ऋण और अग्रिम ऐसे निस्तारित नहीं होते हैं जिस प्रकार से बैंक के द्वारा किये गये अन्य निवेश। इस प्रकार से बैंक सामान्यतः ऐसे ऋणों और अग्रिमों पर अधिक ब्याज दर वसूलता है। ये ऋण और अग्रिम निम्नलिखित रूप में हो सकते हैं:

1. सामान्य ऋण और अग्रिम
2. ओवर ड्राफ्ट
3. कैश क्रेडिट (नकद ऋण)[6]

वास्तविकता यह है कि सभी असफल बैंक ऋण और अग्रिम नीतियों को ही बैंक के फेल होने का दोषी ठहराते हैं। बैंक की सुरक्षा और निस्तारण की दृष्टि से ऋण और अग्रिम कमजोर परिसम्पत्तियाँ हैं। लेकिन इन परिसम्पत्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए जुटायी गयी भारी पूँजी एक कठिन समस्या के रूप में इससे जुड़ी है। ये परिसम्पत्तियाँ निम्न निस्तारण किन्तु अत्यधिक लाभ कमाती हैं।

बिना ब्याज की आय

'अन्य आय' शब्द बैंकों के द्वारा कमाई जा रही उस आय को दर्शाता है जो बिना ब्याज के होती है। इस प्रकार यह विभिन्न मदों का एकीकरण है। तो भी बैंकों की 85 प्रतिशत अन्य आय मुख्य रूप से कमीशन, लेन–देन और दलाली, लेन–देन प्रत्यार्पण और बिक्री में निवेश से होती है। फिर भी यह बैंकों की कुल आय का केवल 15 प्रतिशत है। इस प्रकार से यदि ब्याज आय से इसकी तुलना करें तो बैंक की इस प्रकार की आय मात्रा के हिसाब से अपेक्षाकृत महत्वहीन ही है। तो भी विश्लेषण की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है। वैचारिक दृष्टि से, इसको बैंक की बिना ब्याज की मदों के सापेक्ष अंकिय किया जाता है और कुल खर्च को बैंक पर आर्थिक मध्यवर्ती बोझ समझा जाता है। ब्याज के फैलाव के साथ ही, जो कि आर्थिक मध्यवर्ती कीमत है। बैंक पर बड़ा बोझ बैंक के लाभ और लाभ की सम्भावनाओं को निर्धारित करता है।[7] इस प्रकार के विश्लेषण के 1997–1998 के काल से

प्रारम्भ होने के दो कारण है। प्रथम तो है कि उस वर्ष प्राइवेट सेक्टर में नये बैंक स्थपित किये गये जो कि भारतीय बैकिंग में एक नये युग को अंकित करता है। द्वितीय कारण यह है कि मुख्य तत्वों के आंकड़े विशेष रूप से निवेश की बिक्री के उसी वर्ष से प्राप्त है। विशेष प्रयास मुख्य अवयवों के चलन और सार्वजनिक क्षेत्र के अच्छे क्रियाकलापों पर है।

बैंकों की अन्य आय अब मुख्य रूप से निम्न कारणों पर ध्यान आकर्षित कर रही है जैसे, बैंकों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे इस प्रकार के आय के स्रोतों को बढ़ाये। इस अपेक्षा के पीछे तार्किक आधार, ब्याज दरों का कम होना है। ब्याज दरों की गिरती कीमतों के युग में, बैंक का प्रसार अत्यधिक दबाव में आ जाता है। अपनी आर्थिक और वाणिज्यिक स्थिति को संभाले रखने के लिए अपनी उस पहुँच पर विश्वास करना पड़ता है जो बैंकों की उचित सेवा की साख होती ळै। कुछ तो यह महसूस करते हैं कि यह स्रोत बैंकों के क्रियाकलापों के लिए उचित नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभप्रदत्ता का प्रबन्धन एवं इसकी प्रक्रिया के मूल्याकंन का अध्ययन किया गया है।
2. राष्ट्रीयकृत बैंकों में शाखा स्तर पर लाभ नियोजन का अध्ययन किया गया है।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज एवं गैर–ब्याज से होने वाली आय की कमी का मूल्याकंन करना।

अध्ययन का विश्लेषण

सारणी संख्या 4.1: राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज आय

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	बैंक का नाम	2016	2015	2014	2013	2012
1	इलाहाबाद बैंक	18884.95	19716.12	18746.68	17435.69	15523.28
2	आंध्रा बैंक	17634.68	16368.60	14297.32	12909.69	11338.73
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	44061.28	42963.56	38939.71	35196.65	29673.72
4	बैंक ऑफ इण्डिया	41796.47	43464.71	37910.10	31908.93	28480.67
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	13052.99	12665.44	11956.66	9613.43	7213.96
6	केनरा बैंक	44022.14	43750.04	39547.61	34077.94	30850.62
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	25887.90	26408.78	24427.55	21860.65	19149.50
8	कारपोरेशन बैंक	19411.24	19556.44	17958.57	15334.08	13017.78
9	देना बैंक	10645.73	10763.49	9978.48	8899.39	6794.13
10	इण्डियन बैंक	16243.78	15852.94	15249.21	13892.64	12231.32
11	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	23517.29	23938.33	22683.73	20676.72	17889.11
12	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	20058.71	19961.38	19017.48	17704.78	15814.88
13	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	8744.34	8588.55	7972.71	7340.12	6474.50
14	पंजाब नेशनल बैंक	47424.35	46315.36	43223.25	41893.33	36428.03
15	सिडिकट बैंक	23197.78	21615.16	18620.33	17120.69	15268.35
16	यूको बैंक	18560.97	19358.99	18229.92	16751.71	14632.37
17	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	32198.80	32083.96	29349.39	25124.70	21028.45
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	9936.67	10180.48	10599.29	9251.49	7961.09
19	विजया बैंक	12083.58	12273.53	10706.56	9051.88	7988.13
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		**447363.65**	**445825.86**	**409414.55**	**366044.51**	**317758.62**

आरेख संख्या 4.1: राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज आय

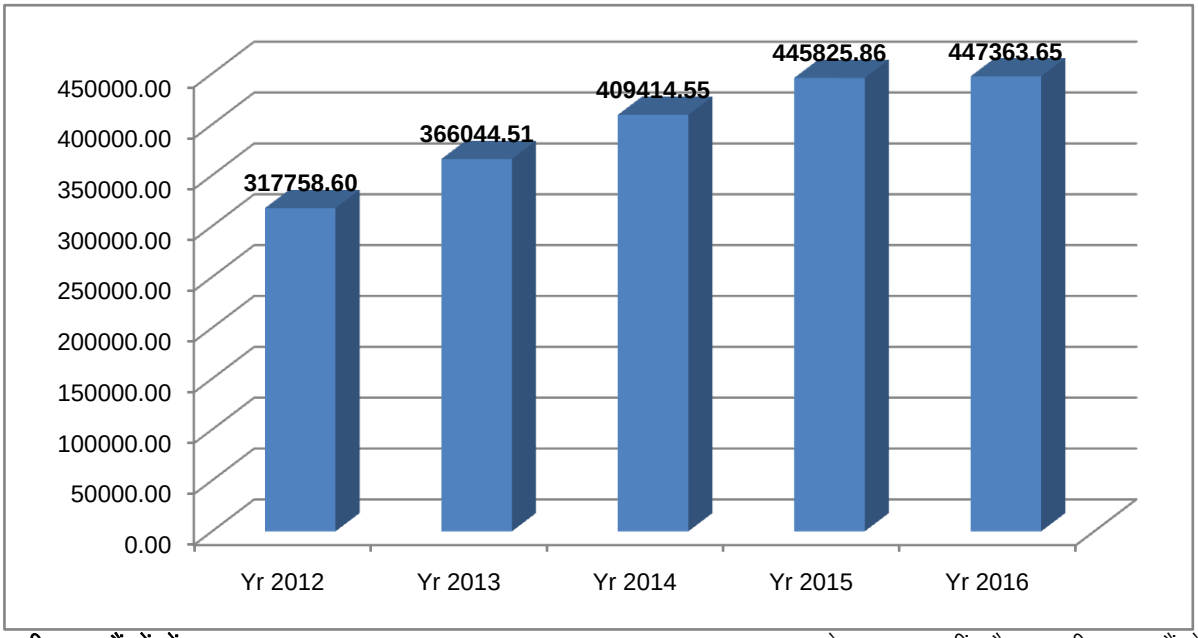

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज आय

राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज आय ही होती है जो कि ऋणों के वितरण पर निर्भर है। उदारीकरण के इस दौर में सरकार एवं रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरों का निर्धारण स्वयं न कर राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध तन्त्रों को ही दे दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंक आजकल आपसी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामने वैश्वीकरण की अवधारणायें आड़े आ रही हैं। विकसित देश कम ब्याज दर रुपया उपलब्ध कराने को तैयार हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकांश ऋण औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान करते थे लेकिन वैश्वीकरण के चलते औद्योगिक क्षेत्र, ऋण कम ब्याज दर पर विकसित देशों से प्राप्त कर लेते हैं। परिणामस्वरूप एक तरफ तो ऋण के क्षेत्र में कमी आयी है तथा दूसरी ओर आपसी प्रतिस्पर्धा। अतः राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज आय में वृद्धि तो हुई है परन्तु वह सन्तोषजनक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामने अपने व्यवसाय की सम्भावनाओं को तलाश करने हेतु ग्राहक सेवा का सहारा लिया जा रहा है।

सारणी संख्या 4.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज जहाँ 2012 में 317758.6 करोड़ रूपये थी वह 2016 में बढ़कर 447363.65 करोड़ रूपये हो गयी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रतिस्पर्धा के चलते ग्राहक सेवा में डिजीटल ग्राहक सेवा में वृद्धि कर अपनी ब्याज आय में वर्ष 2012 के मुकाबले 2016 में 40.79 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। जिसको केवल सन्तोषजनक कहा जा सकता है। स्पष्टतः राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी ब्याज आय को कायम रखने हेतु नये–नये उत्पाद बाजार में उतारने होंगे तथा ग्राहक सेवा में और सुधार करने की आवश्यकता है।

सारणी संख्या 4.2: राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर–ब्याज आय

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	बैंक का नाम	2016	2015	2014	2013	2012
1	इलाहाबाद बैंक	1910.13	1996.01	2165.75	1476.91	1298.68
2	आंध्रा बैंक	1564.47	1499.84	1332.84	1047.42	859.93
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	4998.86	4402.00	4462.74	3630.62	3422.33
4	बैंक ऑफ इण्डिया	3652.54	4197.90	4291.84	3766.04	3321.17
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1019.29	1005.98	894.19	912.00	640.67
6	केनरा बैंक	4875.23	4550.25	3932.76	3153.01	2927.60
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1938.79	1894.23	1922.58	1667.33	1395.30
8	कारपोरेशन बैंक	1735.16	1482.46	1647.72	1607.94	1492.62
9	देना बैंक	716.80	731.33	916.73	655.46	582.17
10	इण्डियन बैंक	1781.42	1363.36	1371.68	1287.94	1232.16
11	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	2528.26	2138.60	2169.34	1972.91	1681.04
12	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1766.28	2121.40	1945.27	1654.71	1240.25
13	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	478.49	428.75	427.28	417.15	417.46

14	पंजाब नेशनल बैंक	6877.02	5890.73	4576.71	4215.92	4202.60
15	सिंडिकेट बैंक	2508.73	2109.59	1324.88	1174.36	1075.88
16	यूको बैंक	1596.31	2003.54	1320.51	952.17	965.56
17	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	3631.74	3523.00	2821.54	2552.03	2448.20
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	1467.53	1746.91	1206.87	1066.57	732.90/
19	विजया बैंक	873.86	878.96	709.87	607.00	527.90
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		**45920.91**	**43964.84**	**39441.10**	**33817.49**	**29731.52**

आरेख संख्या 4.2: राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर–ब्याज आय

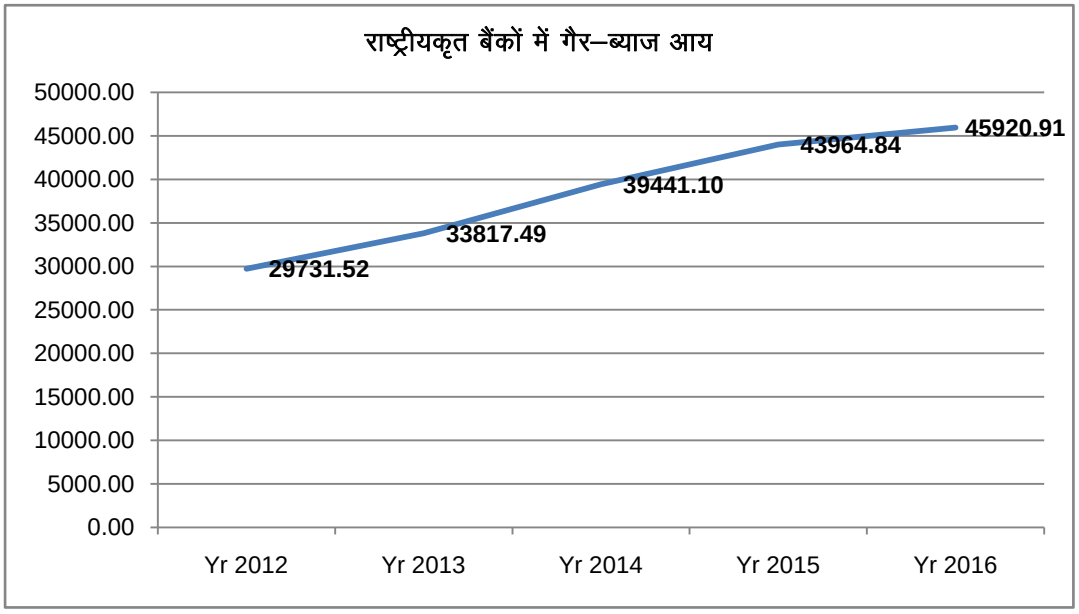

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर–ब्याज आय

राष्ट्रीयकृत बैंक जमा एवं ऋणों के अतिरिक्त सेवायें भी प्रदान करते हैं। जमा एवं ऋण के सम्बन्ध में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपना ध्यान गैर–ब्याज आय की ओर आकर्षित करना पड़ रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में ड्राफ्ट बनाना, बिलों को भुनाना, गारन्टी करना, धन हस्तान्तरण करना, ग्राहकों को सलाह देना, बिलों का भुगतान करना आदि शामिल होते हैं। अतः राष्ट्रीयकृत बैंक इन पर अन्य आय के रूप में कमीशन लेकर सेवायें प्रदान करता है। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गैर–ब्याज आय पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित किया है।

सारणी संख्या 4.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि गैर–ब्याज आय में वृद्धि दर 2012 में रूपये 29731.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013 में 33817.49 करोड़ रूपये हो गयी जोकि 13.47 प्रतिशत बढ़ी है। किन्तु अगर हम वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक के आंकड़ों को लेते हैं तो इसमें 2014–15 के बीच 11.46 प्रतिशत और 2015–16 के बीच 4.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। स्पष्टतः इसका सीधा–सीधा अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्राहक सेवाओं के प्रति गम्भीरता नहीं दिखायी है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले अन्य बैंकों ने ग्राहक सेवा के प्रति अधिक ध्यान दिया है।

सारणी संख्या 4.3 : राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल आय

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	बैंक का नाम	2016	2015	2014	2013	2012
1	इलाहाबाद बैंक	20795.08	21712.13	20912.43	18912.60	16821.96
2	आंध्रा बैंक	19199.15	17868.44	15630.16	13957.11	12198.66
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	49060.14	47365.56	43402.45	38827.27	33096.05
4	बैंक ऑफ इण्डिया	45449.01	47662.61	42201.94	35674.97	31801.84
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	14072.28	13671.42	12850.85	10525.43	7854.63
6	केनरा बैंक	48897.36	48300.29	43480.37	37230.94	33778.22
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	27826.68	28303.01	26350.13	23527.98	20544.80
8	कारपोरेशन बैंक	21146.40	21038.91	19606.29	16942.02	14510.40
9	देना बैंक	11362.53	11484.82	10895.20	9554.850	7376.30
10	इण्डियन बैंक	18025.20	17216.30	16620.89	15180.58	13463.48

11	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	26045.55	26076.93	24853.08	22649.63	19570.15
12	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	21824.99	22082.78	20962.75	19359.49	17055.13
13	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9222.83	9017.30	8399.99	7757.28	6891.96
14	पंजाब नेशनल बैंक	54301.37	52206.09	47799.96	46109.25	40630.63
15	सिंडिकट बैंक	25706.51	23724.76	19945.21	18295.05	16344.23
16	यूको बैंक	20157.28	21362.54	19550.42	17703.88	15597.93
17	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	35830.54	35606.96	32170.93	27676.73	23476.66
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	11404.20	11927.39	11806.16	10318.06	8694.00
19	विजया बैंक	12957.44	13152.49	11416.43	9658.88	8516.03
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		**493284.54**	**489780.73**	**448855.64**	**399862.00**	**348223.06**

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल आय

राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय में ब्याज आय, गैर–ब्याज आय अथवा अन्य आय को शामिल किया जाता है। सारणी संख्या 4.1 व 4.2 के द्वारा ब्याज आय व गैर–ब्याज आय का विश्लेषण किया गया है। फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल आय बढ़ी तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ी है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने पुनर्गठन हेतु व्ययों में वृद्धि की गई है। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनी कुल आय में वृद्धि करने हेतु नयी–नयी अवधारणायें जैसे खुदरा बैकिंग, नयी सूचना प्रौद्योगिकी आदि का सहारा लिया जा रहा है तथा ब्याज आय में ब्याज की दर कम होने से कमी होना स्वाभाविक है।

सारणी सख्या 4.3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय जहाँ वर्ष 2012 में 348223.06 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2013 में 399862 करोड़ रूपये 14.82 प्रतिशत वृद्धि के साथ दर्ज की गई है। परन्तु वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक वृद्धि तो हुई है लेकिन प्रतिशत वृद्धि दर में कमी आंकी गयी है। जो कमशः 12.25 प्रतिशत, 9.11 प्रतिशत और .71 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में ऋणों में प्रतिस्पर्धा होने से ऋणों पर ब्याज की दरों में लगातार कमी हो रही है। अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय घटेगी तो मजबूरन जमाओं पर ब्याज की दर भी कम करनी पड़ेगी।

ओरख संख्या 4.3: राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल आय

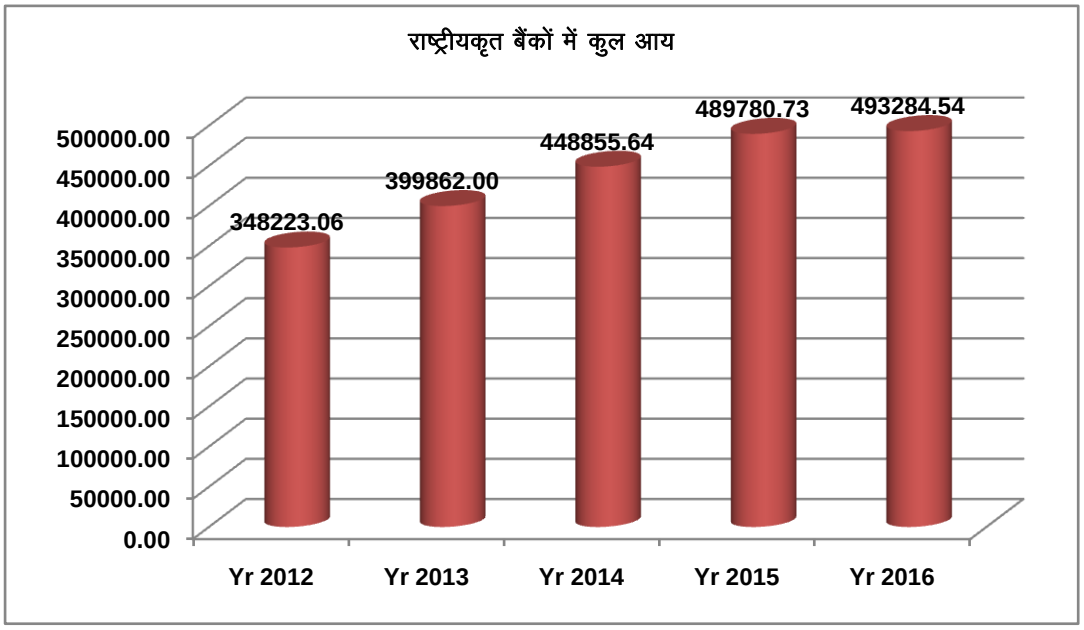

सारणी संख्या 4.4: राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिचालन व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	बैंक का नाम	2016	2015	2014	2013	2012
1	इलाहाबाद बैंक	3674.72	3714.17	3456.65	2958.11	2691.40
2	आंध्रा बैंक	2925.43	2739.44	2309.93	2037.20	1804.25
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	8923.15	7674.12	7137.07	5946.74	5158.72
4	बैंक ऑफ इण्डिया	9341.54	8088.59	6699.47	5331.55	4940.66
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2552.81	2525.93	2396.75	1796.64	1642.52
6	केनरा बैंक	7491.93	7263.55	6081.01	5141.99	4673.74
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	6361.47	5582.18	5178.94	4232.33	3749.00

8	कारपोरेशन बैंक	2879.60	2525.36	2392.01	1996.78	1783.55
9	देना बैंक	2268.25	1838.92	1647.77	1299.70	1154.75
10	इण्डियन बैंक	3195.50	2810.93	2831.50	2750.86	2187.00
11	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	5025.50	4200.21	3748.92	3407.84	3163.06
12	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3458.78	2978.52	2916.88	2665.18	2315.46
13	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1384.38	1332.50	1247.32	1119.33	1158.53
14	पंजाब नेशनल बैंक	9972.45	10491.55	9338.21	8165.05	7002.75
15	सिंडिकट बैंक	5166.88	3622.60	3301.75	3178.83	2814.12
16	यूको बैंक	2840.94	2655.78	2439.20	2176.62	2056.23
17	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	6302.22	6143.43	5482.76	4512.16	3987.52
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	1936.29	1849.63	1707.95	1503.92	1383.30
19	विजया बैंक	2085.82	1912.21	1689.55	1362.97	1201.36
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		**87787.66**	**79949.62**	**72003.64**	**61583.80**	**54867.92**

राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिचालन व्यय

राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु ब्याज व्यय के साथ–साथ कुछ परिचालनगत व्यय करने पड़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिचालनगत व्यय बहुत अधिक बढ़ गये हैं। नयी अथवा पुरानी दोनों ही तकनीकों पर कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह समस्या समान रूप से व्याप्त हैं। पुरानी तकनीकी पर कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की अधिक संख्या, अधिक कर्मचारी व्यय, प्रति कर्मचारी कम व्यापार, प्रति लेनदेन अधिक लागत आदि समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर नयी तकनीक पर कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष अधिक स्थापना लागत, तकनीक अप्रचलित होने की ऊँची दर एवं तदनुरूप अधिक मूल्य ह्रास, प्रति मशीन व्यापार की कम मात्रा आदि प्रमुख समस्याएं हैं।

सारणी संख्या 4.4 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्ययों में व्यवसाय के अनुरूप वृद्धि तो हुई है किन्तु ग्राहक सेवा की अवधारणा को पूर्णतया लागू न कर पाने के कारण यह वृद्धि घटती हुई दर से हुई है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक परिचालन व्यय पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सबसे अधिक किये गये हैं।

सारणी संख्या 4.5: राष्ट्रीयकृत बैंकों में शुद्ध लाभ

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
1	इलाहाबाद बैंक	-360.08	983.92	1401.33	1369.06	1973.19
2	आंध्रा बैंक	634.84	694.60	533.58	1388.20	1637.38
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	-5395.54	3398.44	4541.08	4480.72	5006.96
4	बैंक ऑफ इण्डिया	-6089.21	1708.92	2729.27	2749.35	2677.52
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	100.69	450.69	385.97	759.52	430.83
6	केनरा बैंक	-2812.82	2702.62	2438.19	2872.10	3282.71
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	-2440.96	606.45	-1261.26	1016.44	534.52
8	कारपोरेशन बैंक	-506.48	584.26	561.72	1434.67	1506.04
9	देना बैंक	-935.32	265.48	551.66	810.38	803.14
10	इण्डियन बैंक	806.42	1098.05	1249.19	1670.29	1835.69
11	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	-3387.17	-454.33	601.74	567.23	1050.13
12	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	156.22	498.04	1139.58	1328.44	1142.36
13	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2015.16	1756.86	1843.71	1761.73	1624.16
14	पंजाब नेशनल बैंक	-3974.40	3061.58	3342.58	4747.67	4884.20
15	सिंडिकट बैंक	-1643.49	1522.93	1711.46	2004.42	1313.39
16	यूको बैंक	713.82	4087.74	3625.12	2729.31	2793.84
17	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	1352.02	1782.05	1696.61	2158.54	1787.30
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	-281.96	255.99	-1213.44	391.90	632.53
19	विजया बैंक	1483.98	1373.68	1374.90	1520.58	1447.96
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग		**-20564.28**	**26377.97**	**27252.99**	**35760.55**	**36363.85**

आरेख संख्या 4.7 राष्ट्रीयकृत बैंकों में शुद्ध लाभ

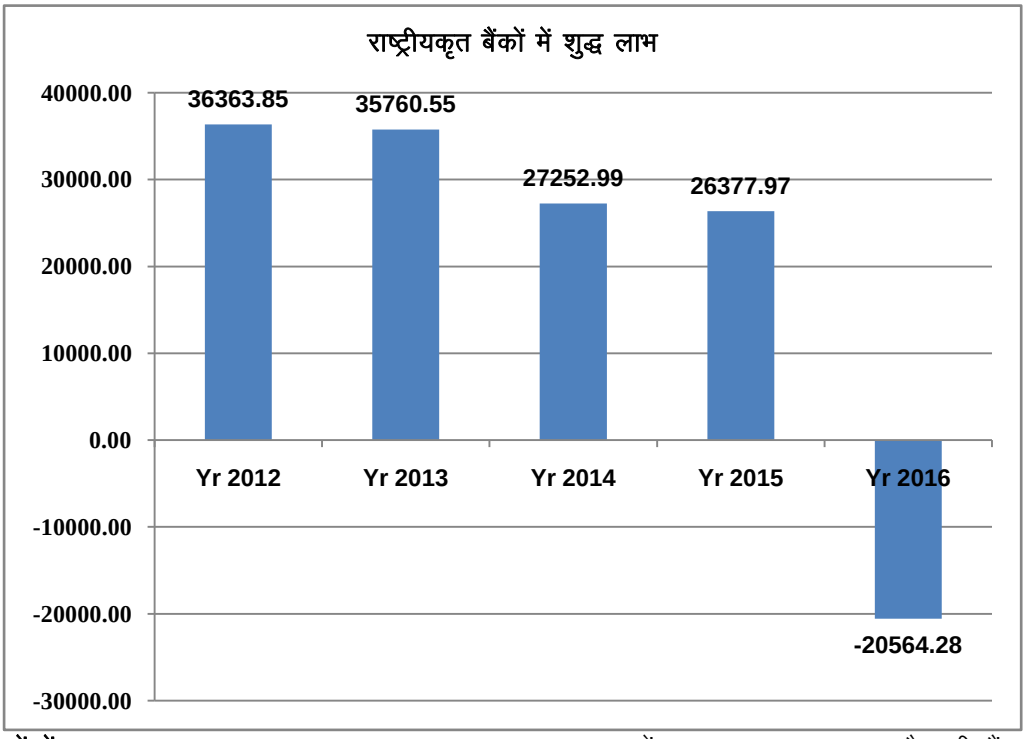

राष्ट्रीयकृत बैंकों में शुद्ध लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण निजीकरण की अवधारणा को लागू किया गया था। इससे पूर्व सभी बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामाजिक बैंकिंग के रूप में होता था किन्तु निजीकरण की अवधारणा आने से बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना हो गया तथा बैकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गयी है। निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में ग्राहकों को अधिक सुविधायें, सेवाएं एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आधारभूत ढांचा पुरानी व्यवस्थाओं पर आधारित होने से वर्ष 2012 से 2015 तक शुद्ध लाभ में निरन्तर कमी आती रही है। लेकिन वर्ष 2016 में यह कमी हानि के रूप में 20564.28 करोड़ रूपये दर्ज की है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परियोजनाओं जैसे मेक इन इण्डिया, डिजीटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया और कैश लैश लेन देनों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के खर्च अत्यधिक होने से कुछ बैंकों को हानि का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भविष्य के हिसाब से लाभ की स्थिति यथासमय अत्यधिक तेज रफतार से बनेगी।

उपसंहार

राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता में सुधार भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी उत्पादकता बढ़ाकर तथा सभी स्तरों पर लागत जागरूकता लाकर अपनी लाभप्रदता से सुधार हेतु विशेष प्रयास करना तथा ऋणों का मूल्याकंन व अनुवीक्षण करके ऋणों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है।सभी बैंक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और कैश लैस के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और इसी वजह से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से इसके ब्याज से होने वाली आयों में लगातार कमी आ रही है लेकिन आगामी वर्षों में अत्यधिक लाभ होने की सम्भावनायें हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। किसी व्यवसायिक बैंक की आय राजस्व और लागत सम्बन्धी कारकों के फलस्वरूप होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Mathur, Dr. B.L. Indian Banking Performance, Problems & Challenges, National Publishing House, Jaipur, 1989*
2. *Chandra Prasanna Financial Manaement, Theory & Practice, Tata Mc Craw Hill Publishing Company Limited, New Delhi 1990*
3. *Sharma, Harish C. Growth of Banking in a Developing Economy, 1969*
4. *Tanna, M.L. Banking Law & Pratice in India, Indian Law House, New Delhi, 2000*
5. *सिंहल, श्री राम प्रकाश बैकिंग और आर्थिक चिंतन के नये आयाम, राष्ट्रीय सेल्स एजेन्सी, जयपुर 2002*
6. *गुप्ता डॉ0 सी0बी0 बैंक प्रबन्धन के सिद्धान्त, सुल्तान चन्द एण्ड संस, नई दिल्ली, 2002*

7. *सारडा, डी0पी0 बैकिंग क्षेत्र में आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, गोविन्द प्रकाशन, जयपुर 1997*
8. *सिंहल, रामप्रकाश वित्तीय क्षेत्र के सुधार– एक दशक, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, 2003*
9. *बंसल, विनय वस्तुनिष्ठ बैकिंग विधि एवं व्यवहार, उपकार प्रकाशन, आगरा, 2003*
10. *गौड़ श्यामलाल बैंकों में ग्राहक सेवा, उपभोक्ता संरक्षण और लोकपाल, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 1997*
11. *The Economics Times, Daily*
12. *Hand Books of Statistics on India Economy, R.B.I., Mumbai 2009 to 2015*
13. *Banking Statistics; Quarterly handout, Reserve Bank of India, Mumbai*
14. *RBI Bulletins, Reserve Bank of India, Mumbai*
15. *Statistical Tables Related to Banks in India, Reserve Bank of India, Mumbai*

पाद टिप्पणी

1. *सिंह रणबीर, आइबीए बुलेटिन, इंडियन बैंकर एसोसियेशन, मुम्बई, जुलाई 2003, पृष्ठ संख्या 20*
2. *सुन्दरम और वार्ष्णेय, Banking Theory, Law and Practice, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 1.14*
3. *सेठ एम0एल0, Macro Economics, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, एजुकेशनल पब्लिशर्स, आगरा, 2001, पृष्ठ संख्या 223*
4. *नटराजन एस0 परमेश्वरम आर0, इंडियन बैंकिग, एस0 चांद एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 67*
5. *नटराजन एस0 परमेश्वरम आर0, इंडियन बैंकिग, एस0 चांद एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 40*
6. *वमन आर0 नायक, इंडियन बैंकिंग, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना, 2002, पृष्ठ संख्या 14*
7. *नागराजन एन0, आइबीए बुलेटिन, मुम्बई, नवम्बर 2002, पृष्ठ संख्या 6*